सरकार ने बढ़ा दिया है और जो ठीक पार्टीज हैं उनकी तीन लाख टन की कैपेसिटी कर दी है ।

Shri P. Venkatasubbaiah: In view of the unsatisfactory performance of the private sector in setting up these pig iron plants, may I know whether Government have considered the desirability of taking over those plants from them and starting them all in the public sector?

Shri P. C. Sethi: There is no question of taking over; we are starting our own.

श्री ग्र० सिं० सहगल : क्या यह सत्य है कि पर्याप्त संख्या में लोगों को लाइसेंस न देने के कारण जितनी तादाद में उत्पादन होना चाहिए उतनी तादाद में नहीं हो रहा है ?

श्री प्र० चं० सेठी : तीन पार्टीज के लाइसेंस पिछले वक्त में कैंसिल किये गये हैं । बाकी इस समय भी 14 पार्टीज को लाइसेंस दिये गये हैं और उनकी प्राग्रस ठीक हो इस की कोशिश की जा रही है ।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि जिन 14 पार्टीज को लाइसेंस दिये गये हैं उनके नाम क्या हैं और वे किन राज्यों की हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : नाम की लिस्ट तो बहुत बड़ी है । लेकिन गोआ में, बम्बई में, भावनगर में, हिसार में, बिहार आदि में लाइसेंस दिये गये है ।

श्री यु० सिं० चौधरी : अभी माननीय मंत्री ने हिसार का जिक्र किया । इसका लाइसेंस किस को दिया गया है, इसमें कितनी लागत लगेगी और यह कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : हिसार का कारखाना पंजाब राज्य सरकार का है ।

Shri S. M. Banerjee: I would like to know whether it has been brought to the notice of the Government that DLF gave some loan for setting up NBC plants in Bengal and other places for producing pig iron. Is it a fact that some plants have been set up as NBC plants which have proved to be very successful; if so, what steps do Government contemplate to have these small plants to produce more pig iron?

Mr. Speaker: The hon. Minister might collect the information.

Shri S. M. Banerjee: They have given licences etc. and they do not know.

Mr. Speaker: At this time he cannot give the information. I have asked him to collect it.

Shri S. M. Banerjee: Then allow me to ask another question.

Mr. Speaker: He has given this information.

श्री रामेश्वरानन्द : अभी खान निकली है नारनौल में और उसके संशोधन के लिए कारखाना हिसार में लगाया जा रहा है, इसका क्या कारण है ? क्या इसका कारण यह है कि वहां की जनता को इसका लाभ न मिल सके ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह तो कारखाना पंजाब सरकार का है, उन्होंने जहां मांगा वहां हम ने दे दिया ।

Shortage of Cement

\+

*364. **Shri Y. S. Chaudhary:**
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri P. R. Chakraverti:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Hem Raj:
Shri Badshah Gupta:
Shri Rameshwaranand:
Shri P. Venkatasubbaiah:

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state:

(a) the steps taken by Government to meet the acute shortage of cement in the country;

(b) whether new cement factories are proposed to be set up in the country to meet the demand; and

(c) if so, the broad features of the scheme?

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3544/64].

श्री यु० सिं० चौधरी : इस स्टटमेंट को देखने से पता चलता है कि सरकार एक सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया बनाने जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि कब तक इस कारपोरेशन की स्थापना हो जायेगी और सीमेंट के उत्पादन से सम्बन्धित बातों पर और जो सीमेंट के वितरण की दोषपूर्ण व्यवस्था है क्या यह उस पर भी निगरानी रखेगा ?

श्री त्रि० न० सिंह : कारपोरेशन का काम अभी वितरण का नहीं होगा ।

श्री यु० सिं० चौधरी : इस स्टटमेंट के दूसरे हिस्से के अन्दर यह कहा गया है कि एडीशनल कैपेसिटी बढ़ाने के वास्ते कुछ कारखानों को नई यूनिटें लगाने के वास्ते आज्ञा दे दी गई है तो मैं पूछना चाहता हूं कि वे कौन-कौन से कारखाने हैं जिनको कि आप का यह वरदान प्राप्त हो रहा है ?

श्री त्रि० न० सिंह : उन कारखानों की एक लिस्ट देना तो मेरे लिए इस समय मुश्किल है लेकिन अगर माननीय सदस्य इस के लिए मुझे अलग से नोटिस देंगे तो मैं उन्हें यह बतला सकता हूं ।

Shrimati Savitri Nigam: It has been mentioned in the statement that the Cement Corporation of India is going to be a firm. May I know how much time the Government will take to from it and whether Government is also intending to examine the present production capacity of the various factories in order to increase their capactiy of production, because some of the factories are working only one shift?

Shri T. N. Singh: Steps are being taken—Sir, there are two questions . . .

Mr. Speaker: One might be answered.

Shri T. N. Singh: Steps are being taken to set up the Cement Corporation very soon. As a matter of fact, decisions regarding appointment of some of the key officers have already been taken?

श्री रामेश्वरानन्द : इस समय सीमेंट की इतनी कमी है कि देहातों में एक-एक कट्टा 20-20 रुपये में मिलता है । इस का कारण केवल नियंत्रण है, तो क्या सरकार यह सोच रही है कि सीमेंट पर से नियंत्रण हटा दिया जाये ताकि लोगों को आसानी से सीमेंट मिल सके ।

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं मानता हूं कि देहातों में सीमेंट की कमी है और उसे हम सभी महसूस कर रहे हैं । चूंकि इस समय देश में सीमेंट की पैदावार कम है इसलिए उस पर से नियंत्रण हटाना गलत होगा ।

Shri Man Sinh P. Patel: In view of the all-India corporation being established, may I know whether some States like Maharashtra and Gujarat have approached the Central Government for starting manufacture of cement and whether Government is going to allow the States to manufacture it?

Shri T. N. Singh: We encourage State Governments to enter the cement trade, if they so desire, for a cement factory in the public sector.

श्री बांगड़ी : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत का सीमेंट का उत्पादन अंग्रेजी राज्य के दौरान में दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कौन से नम्बर पर था और आज अब उस का कौन स नम्बर है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इस नम्बर का पता लगाने के लिए तो मुझे अलग से नोटिस चाहिए ।

Dr. Sarojini Mahishi: May I know how far the incentive by way of extra price offered to the producers to stimulate the maximum utilisation of capacity has been utilised by them all these years?

Shri T. N. Singh: A number of selected mills have utilised it and there has been additional production in the last year of the order of .5 million tons.

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं यह देखता हूं कि सीमेंट का एक तो कानूनी दाम है क़रीब 7–8 रुपये बोरा, दूसरे उस का असली दाम क़रीब 12–14 रुपये बोरा है और तीसरे सिलीगुड़ी जैसी जगहों पर जहां कि सरकारी काम बहुत होता है, चार, पांच रुपये बोरा उसका दाम है, क्या सरकार बतलायेगी कि कुल उत्पादन में से कितने प्रतिशत: को सरकार खुद खपत करती है और वह खपत अच्छी तरह से हो इसके लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह: काफ़ी प्रतिशत:, मेरी समझ में 50 प्रतिशत: से भी अधिक सीमेंट गवर्नमेंट के बहुत से प्रोजक्ट्स के निर्माण में लगता है । अब उस के बारे में अगर वह कोई डिटेल्स चाहेंगे तो मैं उस का पता लेकर उन्हें बतलाऊंगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं यह अर्ज कर दूं कि सिलीगुड़ी में सरकारी काम हो रहा है । वहां बाजार में 4–5 रुपये बोरा सीमेंट का पिछले चार, पांच महीने में मिलता रहा है, अब इस को तो साफ़ यह मतलब है कि सरकारी सीमेंट बाजार में चोरबाजारी की तरह से आता है और वह काफ़ी तादाद में आता है तो इसे रोकने के लिए मंत्री महोदय ने विचार कर के क्या कोई रास्ता निकाला है?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने यह इनफारमेशन दे दी है अब मिनिस्टर साहब इस के लिय कोई न कोई रास्ता निकालेंगे ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मंत्री महोदय को मुझ से ज्यादा मालूम होगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप ने अभी बतलाया है ।

Shri Kapur Singh: It is a world-wide phenomenon.

Shri Nambiar: In view of the fact that the production of cement under the new licensing scheme is not rapid, may I know whether it is due to the shortage of machines and, if it is so, whether it will be possible for the Government to import machinery from the rupee-payment area without difficulties of foreign exchange, so that the production can be arranged quicker?

Shri T. N. Singh: So far as cement projects in the private sector are concerned, we think we are able to provide as much as they require. The difficulty has been that the private sector was not having necessary resources of that order. Foreign exchange, I believe, has not been so much—slightly so—but not so much of a restricting factor. As now the public-sector project is coming up, we shall look into all the suggestions that the hon. Member has made.

श्री के० डे० मालवीय : क्या सरकार को मालूम है कि जहां कहीं भी सरकारी काम में बड़ी-बड़ी निर्माण योजनाओं में सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है वहां आसपास सीमेंट बहुत सस्ता चोरी से मिलता है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हो सकता है ।

Shri P. R. Patel: May I know whether the quotas of cement fixed for the States are fixed on the basis of the requirements of the States or on the population basis?

Shri T. N. Singh: We have taken the requirements also into consideration. They put in their demands also. We take that into account and also the level of consumption by the States

in the previous years. All these factors are considered before the quota is allotted.

श्री तन सिंह : जो सीमेंट की नई फैक्टरियां लगाई जायेंगी क्या उन से हमारी कमी पूरी हो जायेगी; यदि नहीं, तो सरकार उस कमी को पूरा करने के लिए और क्या प्रयास कर रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मेरा ऐसा ख्याल है कि अगले दो, तीन वर्षों तक कम से कम हमें काफ़ी सीमेंट की कमी रहेगी; अलबत्ता उसके बाद चार, पांच वर्ष में, फोर्थ प्लान में, हम डिमांड्स के मुताबिक बहुत कुछ प्रोडक्शन कर सकेंगे ।

Mr. Speaker: Next question.

Shri J. B. Kripalani: I would like to know whether if there is a great deal of blackmarketing in a particular commodity, it is not valid to ask what Government are going to do about it.

Mr. Speaker: I have not prevented that question. I had allowed that question also.

Shri J. B. Kripalani: But no answer was given.

Mr. Speaker: What answer can they give?

Shri T. N. Singh: I have answered it already.

Shri J. B. Kripalani: What steps are they going to take to stop it?

Shri Sheo Narain: They should abolish control.

Export of Iron and Steel

\+

*365. **Shri Kapur Singh:**
Shri Solanki:
Shri Gulshan:
Shri P. K. Deo:
Shri Narasimha Reddy:

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government are considering measures to promote the exports of iron and steel from this country;

(b) if so, the broad features thereof; and

(c) the final export-earnings anticipated as a result of these export measures?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri P. C. Sethi): (a) Yes, Sir.

(b) An export quota of 100,000 tonnes of bars, rods, structurals and rails, was fixed for each of the years 1963-64 and 1964-65.

It has been decided to set up a Steel Exporters' Association with the object of surveying markets, sending out study teams and delegations, undertaking publicity etc. for promoting the export of iron and steel. The Association is expected to come into being shortly.

(c) Exports during 1964-65 are estimated to be of the order of about Rs. 4 crores.

Shri Kapur Singh: Does this export represent our genuine surplus in production, or is it squeezed out by stifling the domestic demand, and if the latter, why is it so?

Shi P. C. Sethi: We are not squeezing out the indigenous demand. As a matter of fact, bars and structurals which are surplus are being exported.

Subsidized Grain Shops for Railwaymen

\+

*366. **Shri Yashpal Singh:**
Shri Nambiar:
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri P. C. Barooah:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a memorandum signed by 400,000 railway employees has